पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

गांव और गरीब के विकास में कोई कोर–कसर न रहे : केशव प्रसाद मौर्य

ग्राम्य विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए, कार्य धरातल पर दिखें :उप मुख्यमंत्री

ग्राम चौपाल से लेकर आवास योजना तक, हर कार्य में हो त्वरित कार्रवाई :केशव प्रसाद मौर्य

मनरेगा भुगतान, आवास योजना व दीदी प्रशिक्षण पर उप मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश

ग्रामीण विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें :मौर्य

गांव की गलियां ग्रामीणों का हाईवे, जलनिकासी व अवस्थापना सुविधाएं हों मजबूत : उप मुख्यमंत्री

एक लाख दीदियों को हर माह प्रशिक्षण देने के निर्देश, ग्राम चौपाल के लिए बनेगा पोर्टल, ग्राम्य विकास विभाग की योजनाएं तेजी से धरातल पर उतारें अधिकारी –केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ : 26 मई, 2026

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारियो को निर्देश दिये है कि ग्राम्य विकास विभाग की सभी कार्ययोजना पर ठोस व प्रभावी एवं त्वरित गति से कार्यवाही की जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लायी जाय। कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए। योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में कोई कोर कसर बाकी न रखी जाय। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव व गरीब का विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गांव में जलनिकासी के पुख्ता प्रबन्ध किये जांय। गावों की गलियां ग्रामीणों का हाइवे है उन्हे व्यवस्थित व ठीक रखा जाए गावों में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जाय। श्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को अपने कैम्प कार्यालय 7–कालिदास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक मे ग्राम्य विकास विभाग के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होने निर्देश दिये कि जहां कार्ययोजना न बनी हो वहां तत्काल कार्य योजना बनायी जाय, मनरेगा के अंतर्गत जो भुगतान अवशेष हो उसको प्राथमिकता के आधार पर भुगतान की कार्रवाई बजट के अनुरूप किया जाय। प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य के बारे में भारत सरकार को पत्र भेजा जाय। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि स्वयं सहायता समूह की 1 लाख दीदियों को प्रतिमाह ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से ग्राम्य विकास संस्थान में दी जाय। इसके लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं के नाम व विवरण सहित सूची राज्य ग्राम विकास संस्थान को तत्काल भेजी जाए तथा ट्रेनिंग के कैलेंडर के अनुरूप ट्रेनिंग दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ट्रेनिंग के भुगतान के बारे में निर्देश दिये कि राज्य ग्राम्य विकास संस्थान व यूपीएस आरएलएम के उच्चाधिकारी बैठक करके नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। ट्रेनिंग का कैलेंडर हर हाल में जारी किया जाए। इसके लिए सख्त दिशा–निर्देश दिये जांय, लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय और सूची की प्रति उप मुख्यमंत्री

जी को भी उपलब्ध करायी जाय। अन्य जिन विभागों की ट्रेनिंग ग्राम्य विकास संस्थानों में दी जाती है उसका भी विवरण उपलब्ध कराया जाय।

विकास खण्डों के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण के संबंध में 15 दिन के अंदर प्रस्ताव मंगाये जाएं। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए की ग्राम चौपालों को पूरे व्यवस्थित तरीके से ठोस व प्रभावी रणनीति बनाकर आयोजित की जांय, इसके लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जांए तथा जिलों से वर्चुअल मीटिंग की जाए। प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण समय से किया जाए। चौपालों के रोस्टर की कॉपी जनप्रतिनिधियों को हर हाल में दी जाय। ग्राम चौपाल समाधान दिवस की तर्ज पर आयोजित किया जांय। इसके लिए एक पोर्टल बनवाया जाए और उसकी लांचिंग कराई जाए, पोर्टल में आवेदक को भी उसकी समस्या के निस्तारण के बारे में जानकारी दिये जाने की व्यवस्था की जाए।

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि खंड विकास अधिकारी के पद का चार्ज देने विषयक शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ग्राम्य विकास विभाग में विभिन्न जांचो के जो प्रकरण लम्बित हैं, उनको तुरंत निस्तारित किया जाय। अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातों को पूरी गम्भीरता से सुनें निस्तारण योग्य प्रकरणो का निस्तारण करें, जो प्रकरण उनके स्तर से निस्तारित नहीं हो सकते उसके बारे मे जनप्रतिनिधियो को संतुष्ट करते हुये अवगत कराया जाए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नये समूहों के गठन की कार्रवाई तेज करें और निष्क्रिय समूहों को तत्काल सक्रिय करने की प्रभावी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय। महिला समर्थ योजना के तहत कार्यों में और तेजी लाई जाए। बैठकों की कार्यवृत्ति समय से भेजी जाए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंडलों में सरस मेले आयोजित किये जांए। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जिलों के ग्राम्य विकास संस्थानो स्थिति का आंकलन करने के लिए मुख्यालय से टीम बनाकर भेजी जाए और समय से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय।

बैठक में राज्यमन्त्री ग्राम्य विकास विभाग श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग श्री सौरभ बाबू, आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग श्री गौरी शंकर प्रियदर्शी, मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्रीमती दीपा रंजन, यूपी आरआरडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री शिव सहाय अवस्थी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

सम्पर्क सूत्र– बी0एल0 यादव

राम यतन/08:30 **PM**

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in